मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल में घोषणा, गाँव वालों को सुबह आदेश मिले

खारी का लाम्बा में प्रातः भ्रमण में 107 वर्षीय कुमकुम देवी ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया

भीलवाड़ा/जयपुर, 6 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा गांव में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गांव के बुजुर्गों, जिनमें विशेषकर 107 वर्ष की कुमकुम देवी और 102 वर्ष के ओंकार तेली शामिल थे, से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या एवं

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रातः खारी के रघुनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने फूल सागर तालाब किनारे युवाओं के साथ योगाभ्यास में भाग लिया और शीशम के पेड़ का पौधारोपण किया।

जीवन के अनुभवों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री का अपनापन देखकर बुजुर्गों ने भी उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान घर-घर जाकर ग्रामीणों से हालचाल जाने। साथ ही, बच्चों को दुलार करते हुए, उन्हें चॉकलेट वितरित कीं। उन्होंने गांव के रघुनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं, फूलसागर तालाब किनारे योग कर रहे युवाओं के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए गांव की आवश्यकताओं और विकास कार्यों पर विस्तार से बातचीत की।

उल्लेखनीय है कि खारी का लाम्बा गांव में शुक्रवार रात आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय की स्थापना, कृषि पर्यवेक्षक पद के सृजन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय विज्ञान (जीव विज्ञान) एवं कृषि विज्ञान प्रारंभ करने के आदेश शनिवार सुबह ग्रामीणों को मिल गये। घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

प्रातः भ्रमण और जनसंवाद में उप-मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, विधायक जब्बर सिंह सांखला, लाला राम बैरवा, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा गांव में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने घर-घर जाकर ग्रामीणों से हालचाल जाने।

तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष व सचिव ने पार्टी छोड़ी

चेन्नई, 06 जून। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शनिवार को उस समय झटका लगा, जब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष करु नागराजन और प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं के इस्तीफे ऐसे समय सामने आए हैं, जब हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के बाद राज्य

- पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बाद इन दो इस्तीफों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी।

इकाई में राजनीतिक हलचल तेज बनी हुई है। प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने भारी मन से तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने और पार्टी से अपने संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि यह फैसला उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद लिया है और उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है।

पं. बंगाल पर मेहरबान हुई केन्द्र सरकार

एक लाख करोड़ की सौगात देने की घोषणा की

कोलकाता, 06 जून। पश्चिम बंगाल में रेल बुनियादी ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं में दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 102 अमृत भारत स्टेशन, 61 नई रेल परियोजनाएं, 538 फ्लाईओवर और अंडरपास तथा कोलकाता मेट्रो के बड़े विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की घोषणा शनिवार को नबान्न (राज्य सचिवालय) में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद की गई। बैठक में रेलवे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसे राज्य में रेल विकास के लिए केन्द्र और राज्य के बीच नए सहयोगात्मक दौर की शुरुआत माना जा रहा है।

बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी

- दिल्ली- सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन सहित 61 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की।

वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली को वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने पर उत्तर बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यह लगभग छह घंटे तक सीमित हो सकता है। इससे क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, पश्चिम बंगाल के 102 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें से 10 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्टेशनों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यभर में 538 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

रेल मंत्रालय ने 61 नई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीमपुर, जालंगी, लालगढ़ , गोपीबल्लभपुर, नयाग्राम, हीली, सागर द्वीप और सुंदरबन जैसे क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है, जो लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं।

कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को भी इस पैकेज में प्रमुखता दी गई है। अगले पांच वर्षों में मेट्रो के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों को शामिल किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक क्षमता उपलब्ध होगी।

साथ ही डानकुनी से सूरत तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई, जिसे औद्योगिक विकास और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अन्नाद्रमुक में अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से इसे अन्नाद्रमुक में अब तक की सबसे बड़ी बगावत माना जा रहा है। हालिया विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही अन्नाद्रमुक के भीतर असंतोष की चिंगारी सुलग रही थी। पार्टी के भीतर तब गहरा संकट खड़ा हो गया था जब 25 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। टीवीके में शामिल हुए पूर्व मंत्री उदुमलाई के. राधाकृष्णन, एम.सी. संपत, कदंबूर सी. राजू और एन.आर. शिवपति ने साफ किया कि विपक्ष में रहते हुए वे जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे थे। दमघोंटू माहौल और पार्टी दिशाहीनता के कारण आखिरकार उन्हें यह कड़ा फैसला लेना पड़ा।

ग्रैंडमास्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ दूसरी जीत और अंतिम से पहले दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश पर महत्वपूर्ण जीत शामिल रही। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ प्रज्ञानानंद ने न केवल नॉर्वे शतरंज के पहले भारतीय विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी जीती।

दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग, विधायक दोषी

नई दिल्ली, 06 जून। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर की गयी हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया है। ?

स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने राजू सिंह की सजा पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया।

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली स्थित अंबेडकर कॉलोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया, जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया। इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायर कर रहे थे। पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायर कर रहा था।

खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए पटना सिविल कोर्ट में याचिका दर्ज की

आशंका है कि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के केस में खान सर व उनके अंगरक्षकों को गिरफ्तार किया जा सकता है

पटना, 06 जून। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में संभावित गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल की। उनके साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड) ने भी अदालत से राहत की मांग की है। यह याचिका एडीजे अनुराग वर्मा की अदालत में दायर की गई है।

खान सर के न्यायालय पहुंचने की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। देशभर में अपनी लोकप्रियता के कारण खान सर से जुड़ा यह मामला पहले से ही चर्चा में था, ऐसे में अदालत

- खान सर जब अदालत पहुंचे तो भारी तादाद में उनके समर्थक, विद्यार्थी और मीडिया प्रतिनिधी भी कोर्ट पहुंचे।

परिसर में भी लोगों की विशेष रुचि देखने को मिली।

खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कदमकुआं थाना पुलिस कर रही है। लिहाजा, गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अदालत से कानूनी संरक्षण की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें आशंका है कि बिना पर्याप्त आधार के उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।

बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि जांच प्रक्रिया जारी रहने के दौरान खान सर को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे जांच में सहयोग करते हुए अपने शैक्षिणक और पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष भी मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है।

मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना में हत्या की कोशिश और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला उनके सुरक्षा गार्डों के कथित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। गार्डों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में आरोप लगाया है कि उन्हें खान सर की ओर से गोली चलाने के लिए कहा गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि बाद की स्थिति को संभाल लिया जाएगा।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि इन आरोपों को लेकर खान सर या उनके अधिवक्ताओं की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

चुनाव प्रचार के मुद्दों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहते हुए भी उस पर केरल में भाजपा के साथ सांठगांठ का आरोप लगाना उचि नही है। उन्होंने कहा, "ऐसे आरोपों को हल्के में नही लिया जा सकता।"

बेबी ने चेतावनी दी कि यह मुद्दा विपक्षी एकता पर असर डाल सकता है और कांग्रेस नेतृत्व को 8 जून की मीटिंग से पहले इन "विवादित कदमों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर इस मुद्दे पर स्थिति साफ नही की जाती, तो इंडिया ब्लॉक का मूल उद्देश्य ही सवालों के घेरे में होगा।"

साथ ही, सीपीएम ने विपक्षी समन्वय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बेबी ने कहा, सीपीएम, इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर मोदी सरकार की तानाशाही, साम्प्रदायिक और जनविरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी।

34 साल पहले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खर्च पर उचित संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाए। पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश प्रार्थी जगदीश के मामले में दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा की प्रार्थी को, अदालत के अवार्ड जारी करने के बावजूद, न तो उसे ड्यूटी पर वापस लिया और ना ही एक रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 34 साल का पहाड़ जैसा लंबा समय बीत चुका है।

इस दौरान उसके परिवार ने कितनी आर्थिक तंगी भोगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि जगदीश को 1 मार्च 1992 को होटल मैनेजमेंट ने नौकरी से हटा दिया था। इसे चुनौती देने पर 19 अक्टूबर 2015 को लेबर कोर्ट ने कर्मचारी को हटाने की कार्रवाई गलत बताते हुए, उसे वापस रखने और पिछले बकाया वेतन भत्ते सहित सभी लाभ देने के आदेश दिए थे।

'नीट -यूजी पुनर्परीक्षा के पेपर लीक दावे निराधार'

एनटीए ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की

नई दिल्ली, 06 जून। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को सोशल मीडिया और विभिन्न मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित उन दावों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है, जिनमें नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने, पहले से उपलब्ध होने या बिक्री किए जाने की बात कही जा रही है।

एनटीए ने एक बयान में कहा कि इस प्रकार की अफवाहें संगठित नकल एवं ठगी गिरोहों द्वारा फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठना है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र लीक या बिक्री से जुड़े सभी दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं।

एनटीए के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा पूरी तरह बरकरार है तथा परीक्षा को सुरक्षित और

- एनटीए ने कहा संगठित नकल एवं ठगी गिरोह ये अफवाह फैला रहे हैं और परेशान अभिभावकों से पैसे लूटना चाहते हैं।

पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

एजेंसी ने बताया कि ऐसे भ्रामक संदेश फैलाने वाले चैनलों, सोशल मीडिया खातों और सामग्री की पहचान कर उन्हें संबंधित प्लेटफॉर्म तथा साइबर अपराध एजेंसियों को रिपोर्ट किया जा रहा है, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

एनटीए ने यह भी कहा कि इस मामले में कानून-प्रवर्तन और साइबर अपराध अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा रही है। फर्जी सामग्री तैयार करना, प्रसारित करना या उसे आगे बढ़ाना तथा छात्रों को ठगने का प्रयास करना गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एजेंसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदेश पर विश्वास न करें, किसी को पैसे न दें और न ही ऐसी सामग्री को आगे साझा करें।

एनटीए ने कहा कि नीट (यूजी) 2026 से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियों के लिए केवल एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित माध्यमों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही की जाएगी।

पंजाब में ओवरलोडेड वैन की ट्रॉले से टक्कर, 9 की मौत

चंडीगढ़ , 06 जून। पंजाब के फिरोजपुर में शनिवार सुबह ओवरलोडेड पिकअप वैन और ट्राले की भीषण टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। मृतक और घायल आपस में रिश्तेदार थे

- पिकअप में आपस में रिश्तेदार 29 लोग अस्थि विसर्जन के लिये डेरा ब्यास जा रहे थे।

और अस्थि विसर्जन के लिए डेरा ब्यास जा रहे थे।पुलिस के अनुसार, पिकअप में करीब 29 लोग सवार थे। गाड़ी की छत और फर्श के बीच में एक विभाजन कर लोगों को बैठाया गया था। इसके अलावा गाड़ी के पीछे लकड़ी के फट्टे लगाकर जगह बढ़ाई गई थी और एक सीढ़ी लगा दी गई थी।

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर नाराज़ भाजपा छोड़ने की संभावना

नई दिल्ली, 06 जून। शिरोमणि अकाली दल के भीतर मचे घमासान और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की अटकलों के बीच, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पटियाला के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी भेंट की।

मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के हितों और राज्य से संबंधित कई अहम विषयों पर विचार-विमर्श किया।

पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा जी से मुलाकात की और पंजाब से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

- इन अटकलों के बीच दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह से मुलाकात की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सरदार केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को लेकर कैप्टन अमरिंदर नाराज चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हाल के दिनों में कई बार सार्वजनिक तौर पर पार्टी में अपनी बात नहीं सुने जाने का मुद्दा उठा चुके हैं।

वे कई मंचों पर पार्टी के साथ नाराजगी जता चुके हैं। इस नाराजगी की जानकारी हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के उस बयान ने दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके संपर्क में हैं और दोनों पुराने मित्र हैं। इसके बाद कैप्टन की कांग्रेस में वापसी को लेकर भी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था।

भारत ने विदेशी पूँजी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 20 प्रतिशत का विद होल्डिंग टैक्स (यानी सोर्स पर काटा जाने वाला टैक्स) देना पड़ता था। यदि सिक्यूरिटीज़ एक वर्ष से अधिक समय तक रखी जाती थीं तो उन पर 12.5 प्रतिशत लॉंग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, जबकि बारह महीने के भीतर बेचने पर 20 प्रतिशत का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। अध्यादेश ने इन सभी कर देनदारियों को समाप्त कर दिया है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (इण्डियन गवरमैंट सिक्यूरिटीज़) में अपने निवेश से मिलने वाला पूरा रिटर्न अपने पास रख सकेंगे।

सरकार ने इन टैक्स छूटों के साथ-साथ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश नियमों को भी उदार बनाया है।

इसने शॉर्ट टर्म निवेश की सीमा, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्यूरिटी वाइज़ निवेश कैप को हटा दिया है, जो पहले सरकारी सिक्यूरिटीज़ में विदेशी भागीदारी को नियंत्रित करते थे। हालांकि कुल निवेश सीमा यथावत रखी गई है, जो केन्द्र सरकार की बकाया प्रतिभूतियों के 6 प्रतिशत और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के 2 प्रतिशत तक ही रहेगी।

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। भारतीय सरकारी बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाकर वह विदेशी पूंजी के बड़े और स्थिर स्रोतों को आकर्षित करना चाहती है, विशेष रूप से पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और सॉवरेन वैल्थ फंड को, जो आमतौर पर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और अचानक धन निकालने की संभावना कम रखते हैं। नीति-निर्माताओं का मानना है कि विदेशी भागीदारी बढ़ने से भारत का बॉन्ड बाजार गहरा होगा, लिक्विडिटी बेहतर होगी तथा एक स्मूद और भरोसेमंद यील्ड कर्व बनाने में मदद मिलेगी। यह यील्ड कर्व पूरी इकॉनमी में लोन और फायनैंशियल एसैट्स की कीमत तय करने के लिए एक बैंच मार्क का काम करता है।

इस कदम का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। चालू खाते के घाटे पर बढ़ते दबाव और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में बनी अनिश्चितता के बीच, भारत पूंजी प्रवाह को मजबूत करने के उपाय तलाश रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विदेशी निवेश रुपये को समर्थन दे सकता है, बाहरी फायनैंसिंग का एक स्थिर स्रोत उपलब्ध करा सकता है और संभवतः सरकार की उधारी लागत को भी कम कर सकता है।

इस प्रकार यह अध्यादेश केवल टैक्स में बदलाव से कहीं ज्यादा है। यह भारत को वैश्विक ऋण पूंजी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने का रणनीतिक प्रयास है।

ब्याज से होने वाली कमाई और कैपिटल गेन्स पर टैक्स हटाकर, और कई रैगुलेटरी बाधआओं को दूर करके, सरकार असल में इंटरनैशनल इन्वैस्टर्स को यह संदेश दे रही है कि भारतीय सरकारी बॉण्ड अब उभरते बाज़ारों में सबसे आकर्षक निवेश अवसर हैं।

बिहार में लालू यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को किस प्रकार परेशान किया जा रहा है। बिहार की जनता प्रतिशोध की भावना से उठाए गए हर कदम का करारा जवाब देगी।"

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पार्टी के और भी नेता अपने सुरक्षा कवर वापस कर सकते हैं।

लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को दी गई वाई-श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है।

इस घटनाक्रम से कुछ दिन पहले, अधिकारियों ने 1997 से 2005 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था।

भवन निर्माण विभाग ने 27 मई के आदेश के माध्यम से लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास के निकट स्थित इस बंगले को डेयरी एवं मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया था।

आदेश जारी होने के समय अवकाश पर गई हुई राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली से लौटने के बाद पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनकी सरकार चाहे तो मुझे बलपूर्वक बेदखल कर दे। मैं यह घर खाली करने वाली नहीं हूँ।"

मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में सुधारों की प्रक्रिया को और गति देने तथा 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुनिश्चित करने के संबंध में भी विचार साझा किए गए।

बैंगलोर के सोने के व्यापारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कंपनी के शेयरों में निवेश किया। विशेष रूप से छोटे निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी के शेयरों में लगा दी।

इतना ही नहीं, लाइफ इंश्योरैंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) जैसे बड़े और अनुभवी संस्थागत निवेशक भी इसका शिकार बन गए। कंपनी की लगातार बढ़ती हुई और आकर्षक दिखने वाली बैलेंस शीट से प्रभावित होकर एलआईसी ने इसके शेयरों में निवेश शुरू किया। समय के साथ, राजेश एक्सपोर्ट्स में एलआईसी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत की सीमा से भी ऊपर पहुंच गई।

कंपनी ने अपनी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के लिए पब्लिक सैक्टर की एक बड़ी संस्था, कैनरा बैंक को भी धोखा दिया।

तथापि, जैसे-जैसे कंपनी के कारोबार और टर्नओवर के आंकड़ों की काल्पनिक प्रकृति सामने आने लगी, उसके शेयरों की कीमत गिरने लगी। इसका मतलब यह था कि सामान्य शेयरधारकों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों को भी अपने निवेश पर भारी नुकसान उठाना पड़ा।

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष राजेश मेहता के निजी डेरिवेटिव सौदों को भी सूचीबद्ध कंपनी की बैलेंस शीट में शामिल कर दिया गया था, जबकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि ये चेयरमैन के व्यक्तिगत लेन-देन थे। इस प्रकार कंपनी के खातों में प्राइवेट ट्रेडिंग को पब्लिक लिस्टेड ट्रेडिंग के साथ मिला दिया गया।

सेबी की रिपोर्टों में उलझी हुई अकाउंटिंग और झूठे दावों को लेकर यही चिंता जताई गई है। जांच में मुख्य रुप से रैवेन्यू के इन बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए आंकड़ों और नतीजतन, दूसरे फायनैंशियल रैश्यो का पता चला है, जिनके आधार पर इन्वैस्टर्स अपना पैसा लगाते थे।

कंपनी ने स्विट्जरलैंड की एक पुरानी सोना रिफाइनरी कंपनी का अधिग्रहण भी किया था, जिससे उसे विश्वसनीयता का एक आवरण मिल गया था। इस विदेशी इकाई के लेन-देन और कारोबार के आंकड़ों को भी भारतीय मूल कंपनी के खातों में शामिल किया गया, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति को वास्तविकता से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक दिखाया जा सके।

लंदन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पैदा करने वाली टिप्पणियों के बारे में सवाल किया। इस बीच, मॉडरेटर ने इस सवाल को रोक दिया और इसे स्वीकार नहीं किया।मॉडरेटर ने कहा, "सम्मान के साथ मेरा कहना है, मैं उस सवाल को नहीं ले सकता क्योंकि विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित है।" स्थल से आए वीडियो में तनावपूर्ण माहौल देखा गया, जहां कुछ उपस्थित लोग खड़े होकर इशारे कर रहे थे और चर्चा के दौरान गतिरोध पैदा हो गया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्सः01562-256908